

शिक्षा व्यवस्था

किसी भी देश में शिक्षा को राजनीतिक रुझानों से ऊपर रखना ही आदर्श व्यवस्था मानी जाएगी। शिक्षा संस्थान ऐसे मंदिर होते हैं जहां न सिर्फ अलग-अलग जाति-धर्म बल्कि, अलग-अलग राजनीतिक झुकाव वाले लोग विद्या की देवी के समक्ष शीश नवाने आते हैं। यह दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए? जबकि न सिर्फ सभी प्रमुख राजनीतिक दलों बल्कि, अन्य भागीदारों को भी सर्वसम्मति से शिक्षा-व्यवस्था का ऐसा पुर्खा आधार तैयार करना चाहिए जिसे बार-बार बदलने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन अपने देश में ठीक इसका उल्टा हो रहा है।

नया मामला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) के नियमों में बदलाव का है, जिसका मसौदा सामने आने पर न सिर्फ शिक्षाविदों बल्कि, राजनीतिक दलों में घमासान मच गया है। दुर्भाग्यवश इसका समर्थन और विरोध भी राजनीतिक सुविधा के आधार पर हो रहा है। यूजीसी के नए मसौदे में कुलाधिपति, जो राज्यपाल ही होते हैं, को राज्य विश्वविद्यालयों की नियुक्ति में ज्यादा अधिकार देने की वकालत की गई। चूंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राज्यों को डर है कि उसके माध्यम से केंद्र सरकार मनमानी करेगी और राजनीतिक नफा-नुकसान में राज्य की सत्ता पर आसीन दल का समीकरण गड़बड़ा जाएगा। मसौदे में शिक्षाविदों के अतिरिक्त उद्योग जगत और सार्वजनिक क्षेत्र की हस्तियों को कुलपति नियुक्त करने के प्रावधान का भी प्रस्ताव है। शिक्षाविद इस प्रस्ताव को अपने अधिकार क्षेत्र में बाहरी दखल के रूप में देख रहे हैं। उन्हें शिक्षा के मंदिर में अपना वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है। नियमों में बदलाव के प्रस्तावों और उनका विरोध दोनों ही पक्षों के तर्कों को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। खासकर ऐसी स्थिति में जब राज्यपालों की भूमिका और उनके माध्यम से अवांछित केंद्रीय दखल का लंबा इतिहास रहा हो। इसी पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के बाद अब केरल ने यूजीसी में संभावित बदलाव के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। यानी राज्यपालों और राज्य सरकारों में टकराव का नया मोर्चा खुल गया है। विश्वविद्यालय विकास का वैचारिक आधार प्रदान करते हैं। इसे हर तरह के आग्रहों से मुक्त रखना अकादमिक स्वतंत्रता की पहली शर्त है। राजनीति करना और इसके दुराग्रहों से मुक्त होना भी हम यहीं सीखते हैं। यहां राजनीति न हो यह आग्रह भी उतना ही गलत होगा जितना यह कि इसे राजनीति का अड्डा ही बना दिया जाए। इसलिए सभी पक्षों को आग्रहों-दुराग्रहों से मुक्त होकर कदम उठाने होंगे।

दुर्दशा का तथ्य नकारना व्यथ

देहाती इलाकों में कर्ज के बोझ तले दबे परिवारों की संख्या में साढ़े चार प्रतिशत इजाफा हुआ है। 2016-17 के सर्वे के दौरान ऐसे परिवारों की संख्या 47.40 प्रतिशत थी, जो ताजा सर्वे के समय 52 फीसदी हो चुकी थी। एक और सरकारी संस्था की रिपोर्ट ने श्रमिक वर्ग की बढ़ती रही दुर्दशा पर रोशनी डाली है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक (नाबाड़) के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे (एनएफआईएस) 2021-22 के दौरान पाया गया देहाती इलाकों में कर्ज के बोझ तले दबे परिवारों की संख्या में साढ़े चार प्रतिशत इजाफा हुआ है। 2016-17 के सर्वे के दौरान ऐसे परिवारों की संख्या 47.40 प्रतिशत थी, जो ताजा सर्वे के समय 52 फीसदी हो चुकी थी। कहा जा सकता है कि अब ज्यादा लोग लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। मगर आय की स्थिति पर गौर करें, तो ऐसे तक निराधार मालूम पड़ेंगे। ताजा सर्वे में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 12,698 रु. सामने आई। इसमें पांच साल में डेढ़ गुना से ज्यादा बढ़ोतारी हुई। तब औसत आमदनी 8,059 रु. थी। राष्ट्रीय परिवार 4.4 व्यक्तियों का है। तो हर व्यक्ति पर आय 2,886 रु. बैठती है। यानी प्रति दिन एक व्यक्ति की खर्च क्षमता 96 रुपये होगी। यह औसत आय है, जिसमें ग्रामीण इलाकों के सबसे धनी और गरीब दोनों तबकों की आमदनी शामिल है।

2013-14 में रंगाराजन समिति ने भारत की गरीबी रेखा 32 रु. प्रति दिन खर्च क्षमता रखने का सुझाव दिया था। दस साल की मुद्रास्फीति से उसे एडजस्ट करें, तो ये रकम आज तकरीबन 60 रुपये बढ़ेगी। इस पैमाने पर पर अनुमान लगाएं, तो संभव है कि भारत में आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। वैसे, जिन परिवारों की औसत आय 12 हजार रुपये हो, वे लाइफ स्टाइल संबंधी चीजों की खरीद के लिए कर्ज लें, यह मानने का कोई तुक वैसे भी नहीं है। तो जाहिर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी-विवाह आदि जैसे खर्चों के लिए कर्ज लेने वाले परिवार बढ़े हैं। इसके पहले लेबर ब्यूरो की परिश्रमिक दर सूचकांक रिपोर्ट, कृषि मंत्रालय के जारी हुए आंकड़ों, तथा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आदि में बताया जा चुका है कि श्रमिक वर्ग की वास्तविक आय गिरी है और औसत आय में वृद्धि गतिरुद्ध ही गई है।

संपादकीय

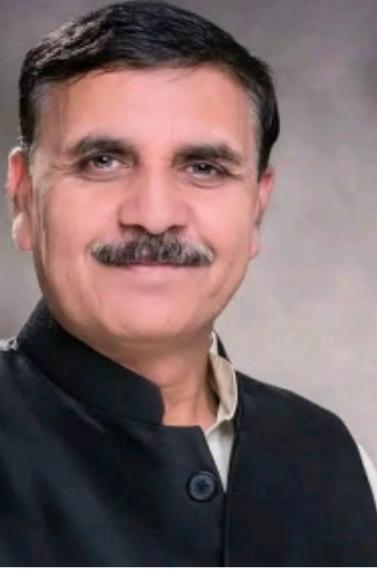
सतत एवं निर्वाध विद्युत आपूर्ति ही हमारा ध्येय

किसानों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पाप कनेक्शन दिये जाने के उद्देश्य से स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाये जाने की योजना लागू की गई है। योजना में किसान स्वयं अथवा समूह में निर्धारित मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। योजना में वर्ष 2023-24 में एक लाख 30 हजार 303 ट्रांसफार्मर स्थापित किये जा चुके हैं। इर्जा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना अटल गृह ज्योति योजना में एक करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को और 26 लाख 59 हजार उपभोक्ताओं को अटल कृषि ज्योति योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। अटल गृह ज्योति योजना में प्रदेश राहत देने के लिये बिजली कंपनियों को अनुमति 24 हजार 420 करोड़ 8 लाख रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। यह सब्सिडी अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, टैरिफ सब्सिडी और निर्शुल्क विद्युत प्रदाय योजना में दी जायेगी।

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक 28627 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर नया रिकार्ड बनाया गया है। यह पावर जनरेटिंग कंपनी के इतिहास का सर्वाधिक तक ताप विद्युत गृहों द्वारा विभिन्न मापदंडों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। ताप विद्युत गृहों का इस दौरान प्लाट लोड फेक्टर (पीएलएफ) 60.3 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2019-20 के पश्चात सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान 13 थर्मल इकाइयों ने लगातार 100 दिनों एवं अधिक सतत व निर्वाध विद्युत उत्पादन किया, जिनमें से दो इकाइयों ने 200 दिनों से अधिक समय तक विद्युत उत्पादन किया। राज्य शासन के निर्णयानुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अब उपभोक्ताओं के लिए विद्युत गृहों द्वारा विभिन्न रिकार्ड रहने पर एक से अधिक बिजली केनेशन उपरान करने की सुविधा कुछ स्तरों के आधार पर कराया जा रही है। ऐसे आवेदक जो एक ही परिसर में पृथक-पृथक रहने पर एक से अधिक बिजली केनेशन उपरान करने की विद्युत वितरण कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई के अभियांत्रों व कार्मिकों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रिवेट-प्रिवेट रिकार्ड रहने पर एक से अधिक बिजली केनेशन उपरान करने से सफलता हासिल की है। यह विद्युत यूनिट की स्थापना के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

इस्तेंट प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक 28627 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर नया रिकार्ड बनाया गया है। यह पावर जनरेटिंग कंपनी के इतिहास का सर्वाधिक तक ताप विद्युत गृहों द्वारा विभिन्न मापदंडों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। ताप विद्युत गृहों का इस दौरान प्लाट लोड फेक्टर (पीएलएफ) 60.3 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2019-20 के पश्चात सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान 13 थर्मल इकाइयों ने लगातार 100 दिनों एवं अधिक सतत व निर्वाध विद्युत गृहों द्वारा विभिन्न मापदंडों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। ताप विद्युत गृहों का इस दौरान प्लाट लोड फेक्टर (पीएलएफ) 60.3 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2019-20 के पश्चात सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान 13 थर्मल इकाइयों ने लगातार 100 दिनों एवं अधिक सतत व निर्वाध विद्युत गृहों द्वारा विभिन्न मापदंडों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। ताप विद्युत गृहों का इस दौरान प्लाट लोड फेक्टर (पीएलएफ) 60.3 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2019-20 के पश्चात सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान 13 थर्मल इकाइयों ने लगातार 100 दिनों एवं अधिक सतत व निर्वाध विद्युत गृहों द्वारा विभिन्न मापदंडों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। ताप विद्युत गृहों का इस दौरान प्लाट लोड फेक्टर (पीएलएफ) 60.3 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2019-20 के पश्चात सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान 13 थर्मल इकाइयों ने लगातार 100 दिनों एवं अधिक सतत व निर्वाध विद्युत गृहों द्वारा विभिन्न मापदंडों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। ताप विद्युत गृहों का इस दौरान प्लाट लोड फेक्टर (पीएलएफ) 60.3 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2019-20 के पश्चात सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान 13 थर्मल इकाइयों ने लगातार 100 दिनों एवं अधिक सतत व निर्वाध विद्युत गृहों द्वारा विभिन्न मापदंडों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। ताप विद्युत गृहों का इस दौरान प्लाट लोड फेक्टर (पीए

मोदी सरकार की दूरदर्शिता और विकासशील भारत के संकल्प का सशक्त ब्लूप्रिंट है आम बजट: विनोद सोनकर



कौशली। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री व पूर्व सांसद कौशली विनोद सोनकर ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की आज के बजट में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए उनके सपनों को साकार करने की एक नई दिशा दी है। आयकर में राहत सहित, यह बजट मोदी सरकार की दूरदर्शिता और विकासशील भारत के संकल्प का सशक्त ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, नवाचार और निवेश तककृहर थेवर को समर्हित करता यह बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट के लिए प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी और विनोद मंत्री निर्मला सीतारमण बधाई की पात्र हैं।

निस्वार्थ भाव से का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा भारत सेवाश्रम



महाकुम्भ नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुम्भ नगर के सेक्टर 5 रियल भारत सेवाश्रम के शिविर गए। जहां उन्होंने सेवाश्रम के साधु संतों से मुलाकात की। साधु संतों ने महाकुम्भ में उनके द्वारा किए जा रहे सामुदायिक और सेवा के कार्यों की जानकारी भी सीएम से साझा की। सीएम ने कहा कि भारत सेवाश्रम साधु संतों के साथ सामुदायिक और गरीबों की सेवा में लगे दार्त्तिक और आध्यात्मिक संगठनों से भी मुलाकात की। आयोजन की अगुवाई कर रहे भारत सेवाश्रम के स्वामी असीमानंद जी ने साथ साथ समाज सेवा का लंबा समय बिताया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुम्भ में सनातन को आगे ले जाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील विभिन्न सम्प्रदायों के सेवाश्रम सौ से अधिक वर्षों से निर्वाचित है। सीएम योगी के शिविर आगमन पर भारत सेवाश्रम के संतों ने महा कुम्भ में उनके धार्त्तिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी भी साझा की। भारत सेवाश्रम के महा कुम्भ प्रभारी स्वामी भास्करानंद ने बताया कि भारत सेवाश्रम मानव सेवा के साथ नारायण सेवा का कार्य करने वाला एक हिंदू धार्त्तिक और आध्यात्मिक संगठन है जो मानवीय कार्यों पर केंद्रित है। 1917 में इसकी स्थापना करने वाले पंडित संत आचार्य स्वामी प्रणवानंद महाराज ने माध के महीने में इसी समाज के किनारे संन्यास लिया था। इसलिए इस संगम की धरती और महाकुम्भ इस आध्यात्मिक संगठन से खास संबंध है। स्वामी प्रणवानंद जी ने माधी पूर्णिमा के ही दिन संगठन की नींव रखी और उसका नाम रखा भारत सेवाश्रम संघ रखा गया।

महानिदेशक सीबीसी ने महाकुम्भ मेले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

महाकुम्भ नगर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार व्यूरो (सीबीसी) के महानिदेशक योगेश कुमार बावेजा ने शनिवार को प्रयागराज महाकुम्भ मेले में जनकल्याणी से जनकल्याणी और भारत सरकार के विगत 10 वर्षों में उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों एवं योजनाओं पर लगायी गयी डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उनके साथ सीबीसी के अपर महानिदेशक अजय अग्रवाल भी उपस्थित रहे। आर्कर्क एवं सूचनाप्रद डिजिटल प्रदर्शनी को देखकर महानिदेशक बावेजा ने कहा कि इस प्रदर्शनी में भारत सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को उत्तम तरीके से प्रदर्शित किया गया है। एनार्किंग वाल, एलईडी टीवी स्क्रीन वाल, होलोग्राफिक सिलेंडर जैसी नई तकनीक से विकसित इस मल्टीमीडिया प्रदर्शनी से आम लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में बेहतर जानकारी मिल रही है। महानिदेशक ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों एवं वर्षों से अवगत कराना है। जिससे वह इन नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ ले सके। भ्रान्ति के दौरान महानिदेशक ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से महाकुम्भ में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया तथा सीबीसी और पीआईसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सीबीसी और पीआईसी के अधिकारियों के साथ समन्वयन स्थापित करने तथा प्राचा-प्रसार से जुड़े कार्यों के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक नीर्देश भी दिए। प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गई। यह डिजिटल प्रदर्शनी जो 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच अद्वालुओं और आगंतुकों को भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं, नीतियों और राष्ट्रीय एकत्र के प्रयासों की जानकारी देने के लिए एक अनूठा माध्यम बनी हुई है। यह प्रदर्शनी शपकता ही समाज का बल है की शीर्ष पर आधारित है, जिसमें शक्ति राष्ट्र, एक कर्श, एक देश, एक राशन कार्ड जैसी पहलों के जरिये देश को सरकार के प्रयासों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही, जनकल्याणी से जनकल्याण की भावना को साकार करते हुए उद्यमिता, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। एलईडी स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और दृश्य-श्रव्य माध्यमों से यह प्रदर्शनी न केवल आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश दे रही है, बल्कि आधुनिक तकनीक से जन-जन को जोड़ने का माध्यम भी बन रही है। अद्वालु यहां सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। सीबीसी प्रयागराज द्वारा डी.जी. एवं ए.डी.जी. का प्रदर्शनी परिसर में स्वागत किया गया एवं प्रदर्शनी की अव तक की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।



त्रिवेणी तट पर नागा साधु बने आकर्षण का केंद्र

महाकुम्भ नगर। महानिदेशक सीबीसी ने त्रिवेणी तट पर नागा साधु बने आकर्षण का केंद्र किया। यह एक अंतिम अमृत स्नान पर नागा अद्वालुओं को देखने उमड़ी अद्वालुओं की भीड़ ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे नागा साधुओं के अद्भुत प्रदर्शन ने हर किसी को किया मंत्रमुद्धय सवार और पैदल चल रहे नागा साधुओं ने शस्त्रों के साथ अपनी युद्ध कला का भी किया प्रदर्शन।

महाकुम्भ नगर। महाकुम्भ के अंतिम अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि महाकुम्भ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का उत्सव है।

शोभायात्रा के दौरान मीडियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर छींचा। अमृत स्नान के लिए ज्यादातर अद्वालुओं का नेतृत्व कर रहे नागा साधुओं को अनुशासन और उनका पारम्परिक सांस्कृतिक व्यवहार करते हुए उद्यमिता, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश दे रही है, बल्कि आधुनिक तकनीक से जन-जन को जोड़ने का माध्यम भी बन रही है। अद्वालु यहां सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। सीबीसी के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक अनूठा माध्यम बनी हुई है। यह प्रदर्शनी शपकता ही समाज का बल है की शीर्ष पर आधारित है, जिसमें शक्ति राष्ट्र, एक कर्श, एक देश, एक राशन कार्ड जैसी पहलों के जरिये देश को सरकार के प्रयासों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही, जनकल्याणी को अपने में समर्पण रूप से धारण किया गया है। एलईडी स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और दृश्य-श्रव्य माध्यमों से यह प्रदर्शनी न केवल आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश दे रही है, बल्कि आधुनिक तकनीक से जन-जन को जोड़ने का माध्यम भी बन रही है। अद्वालु यहां सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। सीबीसी के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक अनूठा माध्यम बनी हुई है। यह प्रदर्शनी शपकता ही समाज का बल है की शीर्ष पर आधारित है, जिसमें शक्ति राष्ट्र, एक कर्श, एक देश, एक राशन कार्ड जैसी पहलों के जरिये देश को सरकार के प्रयासों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही, जनकल्याणी को अपने में समर्पण रूप से धारण किया गया है। एलईडी स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और दृश्य-श्रव्य माध्यमों से यह प्रदर्शनी न केवल आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश दे रही है, बल्कि आधुनिक तकनीक से जन-जन को जोड़ने का माध्यम भी बन रही है। अद्वालु यहां सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। सीबीसी के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक अनूठा माध्यम बनी हुई है। यह प्रदर्शनी शपकता ही समाज का बल है की शीर्ष पर आधारित है, जिसमें शक्ति राष्ट्र, एक कर्श, एक देश, एक राशन कार्ड जैसी पहलों के जरिये देश को सरकार के प्रयासों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही, जनकल्याणी को अपने में समर्पण रूप से धारण किया गया है। एलईडी स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और दृश्य-श्रव्य माध्यमों से यह प्रदर्शनी न केवल आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश दे रही है, बल्कि आधुनिक तकनीक से जन-जन को जोड़ने का माध्यम भी बन रही है। अद्वालु यहां सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। सीबीसी के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक अनूठा माध्यम बनी हुई है। यह प्रदर्शनी शपकता ही समाज का बल है की शीर्ष पर आधारित है, जिसमें शक्ति राष्ट्र, ए